(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will not go on record.

(v) NEED FOR ACCORDING CENTRAL RECOGNITION TO KERALA INSTITUTE OF NAUTICAL STUDIES AT KOVALAM

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR (Trivandrum) : It has been felt that the establishment of a nautical training institution will go a long way in promoting the sea-fearing profession among the unemployed youth in Kerala which has a lengthy coastline.

Further, imparting training on the various aspects of seamanship, navigation and operation and repairs of marine engines and use of life-saving appliances to the existing personnel for operating the large number of mechanised fishing vessels and other seagoing crafts is a must for increasing their efficiency and it will avoid accidents at sea.

Considering all the above aspects, the State Government decided to set up a nautical training institution by name 'Kerala Institute of Nautical Studies' based at Kovalam, Vizhinjan, 18 Km. south of Trivandrum. The institute was formally inaugurated by the Prime Minister during September, 1977. To start with, a 6 months course of 'Seaman Training' has been introduced and 40 trainees have already completed their course. It has been decided to select 100 trainees from the next batch onwards.

Central and Kerala officials and Ministers concerned had all agreed to the setting up of the Institute and starting the 'Seaman Training Course'. However, official recognition has not yet been given. This was taken up again formally with the Director General of Shipping during August, 1979 and the approval of the Ministry is awaited. In order to derive the maximum benefit for the trainees to get employment in marine profession, it is essential that the Central Government recognises this institution, without any further delay.

(vi) NEED FOR STEPS TO INCREASE SUPPLY OF KEROSENE, DIESEL AND BITUMAN TO HILLY DISTRICTS OF U.P.

श्री हरीशचंद्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों में प्रान्तीय सरकार द्वारा समुचित आवंटन के बावजूद मिट्टी के तेल व डीज़ल की उपलब्धता नहीं के बराबर है। इसका कारण इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा समय पर सप्लाई का न किया जाना है। इन दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मिट्टी का तेल व डीज़ल ले जाने वाले ठेकेदारों के पास टैंकरों की कमी है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन व अन्य के वहां डिपो बने नहीं हैं। डीज़ल के अभाव में पर्वतीय क्षेत्रों में सप्लाई की स्थिति कुप्रभावित हो रही है। अतः पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज़िला मुख्यालयों में आयल डिपो बनायें तथा टैंकरों की संख्या बढ़ायें।

इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में बिटुमेन के अभाव में सड़कों को पक्का करने का काम भी रुका हुआ है। सड़कों के पक्का न होने से भूस्खलन हो रहा है, जिसके कुप्रभाव से मैदानी भागों में बाढ़ आती है। पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बीस हज़ार मेट्रिक टन बिटुमैन का विशेष वार्षिक आवंटन करें।

पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों के विनाश को रोकने के लिए आवश्यक है कि वैकल्पिक ईंधन स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाये। इस संदर्भ में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों में गैस कनेक्शन गत वर्ष नवम्बर, तक उपलब्ध करवाने का वादा किया था, जिसे उस समय पूरा नहीं किया गया।

अतः अब वादे के अनुसार शीघ्र गैस-कनेक्शन उपलब्ध करवाये जायें।

**Not recorded.